



14 मिनट	8	24	1	GS1 • 4	GS2 • 23	GS3 • 23
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	मेन्स प्रश्न	पेपर मिश्रण		

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 केंद्र सरकार ने फ्लड प्लेन की परिभाषा बदली, गंगा किनारे रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन की अनुमति

क्यों ज़रूरी: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के माध्यम से, गंगा नदी के साथ मध्यम/दुर्लभ बाढ़ क्षेत्रों में विनियमित निर्माण की अनुमति देने के उद्देश्य से बाढ़ के मैदान (flood plain) की परिभाषा में संशोधन किया है।

GS3 • पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

P

M

2 वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा: अब विरोध करने पर 3 साल तक की जेल

क्यों ज़रूरी: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'वन्दे मातरम्' के अपमान को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो इसे राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

3 रिपोर्ट्स में दावा चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पार की

क्यों ज़रूरी: अरुणाचल प्रदेश में LAC को पार करने वाले चीनी सैनिकों की रिपोर्ट ने कूटनीतिक तनाव उत्पन्न कर दिया है, जो भारत-चीन सीमा प्रबंधन में जारी तनाव को रेखांकित करता है।

GS3 • आंतरिक सुरक्षा

P

M

4 Skyroot का Vikram-1 ऑर्बिट में सफल, लेकिन इन-हाउस SCOPE सैटेलाइट की टेलीमेट्री फेल

क्यों ज़रूरी: Skyroot Aerospace ने सफलतापूर्वक अपने विक्रम-1 रॉकेट को कक्षा में प्रक्षेपित किया, किंतु इसके SCOPE उपग्रह के साथ टेलीमेट्री विफलताओं का सामना करना पड़ा, जो भारत में निजी अंतरिक्ष अन्वेषण की जटिलताओं को रेखांकित करता है।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

5 NASA ने भारत को साउथ पोल के पास मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया

क्यों ज़रूरी: 9वें भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान, NASA ने ISRO को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट अपने 'मून बेस' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

GS3 · पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

P

M

केंद्र सरकार ने फ्लड प्लेन की परिभाषा बदली, गंगा किनारे रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन की अनुमति

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के माध्यम से, गंगा नदी के साथ मध्यम/दुर्लभ बाढ़ क्षेत्रों में विनियमित निर्माण की अनुमति देने के उद्देश्य से बाढ़ के मैदान (flood plain) की परिभाषा में संशोधन किया है।

याद रखें

- NMCG: National Mission for Clean Ganga नदी कायाकल्प के लिए नोडल एजेंसी है।
- यह संशोधन मध्यम या दुर्लभ बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देता है।
- 'Active flood plain' के भीतर निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

मेन्स कोण गंगा जैसी भारत की प्रमुख नदियों के बाढ़ के मैदानों में शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/101631

GS3 · आंतरिक सुरक्षा

P

M

रिपोर्ट्स में दावा चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पार की

चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश में LAC को पार करने वाले चीनी सैनिकों की रिपोर्ट ने कूटनीतिक तनाव उत्पन्न कर दिया है, जो भारत-चीन सीमा प्रबंधन में जारी तनाव को रेखांकित करता है।

याद रखें

- ऊपरी सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जिला है।
- LAC (Line of Actual Control) भारत और चीन के बीच एक de facto सीमा है।
- रंधीर जायसवाल, Ministry of External Affairs (MEA) के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं।

मेन्स कोण वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के प्रबंधन की चुनौतियों और भारत एवं चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/101541

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा: अब विरोध करने पर 3 साल तक की जेल

चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'वन्दे मातरम्' के अपमान को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो इसे राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

याद रखें

- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम: राष्ट्रीय प्रतीकों को अपमान से बचाने वाला कानून।
- वंदे मातरम के अपमान/बाधा डालने पर दंड: 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना।
- लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार 'वन्दे मातरम्' गाया जाएगा।

मेन्स कोण राष्ट्रीय प्रतीकों के संरक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि इस प्रकार के विधान राष्ट्रीय अखंडता के संरक्षण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/101619

GS3 · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

Skyroot का Vikram-1 ऑर्बिट में सफल, लेकिन इन-हाउस SCOPE सैटेलाइट की टेलीमेट्री फेल

चर्चा में क्यों: Skyroot Aerospace ने सफलतापूर्वक अपने विक्रम-1 रॉकेट को कक्षा में प्रक्षेपित किया, किंतु इसके SCOPE उपग्रह के साथ टेलीमेट्री विफलताओं का सामना करना पड़ा, जो भारत में निजी अंतरिक्ष अन्वेषण की जटिलताओं को रेखांकित करता है।

याद रखें

- Skyroot Aerospace: एक निजी भारतीय स्पेस-टेक कंपनी।
- Vikram-1: Skyroot Aerospace का पहला कक्षीय प्रक्षेपण यान (orbital launch vehicle)।
- टेलीमेट्री (Telemetry): एक अंतरिक्ष यान से ग्राउंड स्टेशन तक डेटा का स्वचालित प्रसारण।

मेन्स कोण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भूमिका और वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/101498

NASA ने भारत को साउथ पोल के पास मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया

चर्चा में क्यों: 9वें भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान, NASA ने ISRO को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट अपने 'मून बेस' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

याद रखें

- NASA का Moon Base कार्यक्रम अन्वेषण के लिए चंद्र दक्षिणी ध्रुव (lunar South Pole) को लक्षित करता है।
- Artemis Accords: चंद्र अन्वेषण और सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की एक श्रृंखला।
- TRUST Initiative: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डेटा साझाकरण में भारत-अमेरिका सहयोग के लिए एक रूपरेखा।

मेन्स कोण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग, विशेष रूप से 'आर्टेमिस समझौता' (Artemis Accords) के माध्यम से, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ करता है, चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/101495

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन खतरों के खिलाफ इमरजेंसी मैकेनिज्म बनाने को केंद्र सरकार से कहा

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से डीपफेक और डॉक्सिंग जैसे तेजी से फैलने वाले ऑनलाइन खतरों का मुकाबला करने के लिए एक आपातकालीन तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया है।

याद रखें

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास साइबर खतरों के विरुद्ध सरकारी तंत्र की पर्याप्तता की जांच करने की न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है।
- याचिका विशेष रूप से doxxing और deepfake impersonation को तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण ऑनलाइन खतरों के रूप में पहचान करती है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत की साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए प्राथमिक नोडल मंत्रालय है।

मेन्स कोण वर्तमान कानूनी ढांचे के भीतर डीपफेक और डॉक्सिंग जैसे तीव्र-प्रगति वाले साइबर अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और एक समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/101336

रिन्यूएबल एनर्जी में उछाल: भारत ने 300.50 GW का आंकड़ा छुआ, सोलर 164.59 GW के साथ सबसे आगे

चर्चा में क्यों: जुलाई 2026 तक, भारत ने सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार के कारण 300.50 GW गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त किया है।

याद रखें

- 31 जुलाई, 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म (non-fossil) बिजली क्षमता 300.50 GW तक पहुँच गई।
- गैर-जीवाश्म क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 164.59 GW है।
- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 190.96 बिलियन यूनिट (2014-15) से बढ़कर 477.79 बिलियन यूनिट (2025-26) हो गया।

मेन्स कोण ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की ओर भारत के तीव्र संक्रमण के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/101334

NFHS-6 में शुरुआती ब्रेस्टफीडिंग में बढ़ोतरी लेकिन 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव फीडिंग में गिरावट

चर्चा में क्यों: NFHS-6 के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रारंभिक स्तनपान की शुरुआत में वृद्धि के बावजूद, छह महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए विशेष रूप से केवल स्तनपान (exclusive breastfeeding) में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

याद रखें

- NFHS-6: जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान की दर बढ़कर 50.1% हो गई।
- NFHS-6: छह महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए विशेष रूप से स्तनपान (exclusive breastfeeding) की दर घटकर 55.8% हो गई है।
- NFHS: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला, बहु-चरणीय सर्वेक्षण।

मेन्स कोण भारत में प्रारंभिक स्तनपान के बावजूद विशेष रूप से केवल स्तनपान (exclusive breastfeeding) की निरंतरता में आने वाली सामाजिक-आर्थिक और प्रणालीगत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/101324

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल

असासिनेशन की कोशिश नाकाम होने पर 18 की उम्र में शहीद हुए युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस

जस्टिस रमेश ने तमिलनाडु सरकार को सड़कों से जाति के नाम हटाने का निर्देश दिया
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रिपैट्रिएशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालयों से पूछे सवाल

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पाकिस्तान, Turkey और Saudi Arabia ने किया डिफेंस पैक्ट साइन, भारत की चिंता बढ़ी

दिल्ली में CWMA ने Cauvery Water को मंजूरी दी

भारत ने जोड़े 11 नए E-Visa एंट्री पॉइंट्स, कुल संख्या हुई 88

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की मांग करते हुए

कर्नाटक हाई कोर्ट ने FIR के बिना अस्पताल के उपकरण मांगने की पुलिस की मांग रद्द की

धार्मिक अपमान के चलते Google ने भारत में YouTube वीडियो हटाया

केरल ने इंजीनियरिंग एडमिशन की डेडलाइन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय से मांग की

केंद्र ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के पॉइंट ऑफ कॉल स्टेटस के अनुरोध को किया खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ने विवादित MSPSA को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को हटाया

12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18th BRICS Summit में

चीफ जस्टिस Surya Kant की अध्यक्षता में भारत का सुप्रीम कोर्ट

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

April-June 2026 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.4% हुई

4 HLCDC सदस्यों ने जम्मू में डिटेनशन सेंटर में रोहिंग्या लोगों से मुलाकात की

El Niño के बावजूद आंध्र प्रदेश की 10.7% ग्रोथ, Naidu का 15% ग्रोथ का लक्ष्य

मध्य प्रदेश में पैदा होते ही बच्चे पर 55,323 रुपये का कर्ज

Alpine स्टडी: AI के इस्तेमाल से ग्लोबल एनर्जी एमिशन 1.2 से 4.8 percent तक बढ़ सकते हैं

AI मॉडल्स में समानताएं और कमियां पाई गई, रिसर्चर्स का दावा

तमिलनाडु ने 65 यूनिट्स के साथ ₹264 करोड़ की 'Anti-Narcotics Task Force' शुरू की

नई स्टडी में Schizophrenia से जुड़े 766 Genes का खुलासा, जिनमें से 641 पहले अज्ञात थे

आंध्र प्रदेश ने हाई-राइज स्लम रिडेवलपमेंट को दी मंजूरी, वेलांपेटा में 177 यूनिट्स से शुरुआत

AI कंपनी Anthropic ने Claude के कंटेंट में अदृश्य वॉटरमार्क डाले

GS3 • पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

गंगा जैसी भारत की प्रमुख नदियों के बाढ़ के मैदानों में शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह **टेलीग्राम** पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।